भारत की जनसँख्या नीति
Population Policies of India

बोलेन्द्र कुमार अगम,
सहायक प्राध्यापक भूगोल,
राजा सिंह कॉलेज सिवान

भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है । इस बढ़ती हुई जनसंख्या ने गंभीरता से सोचने पर विवश कर दिया कि जनसंख्या के लिए कोई उपयुक्त नीति बनाई जाए जिससे उसकी वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सके क्योंकि योजना आयोग के अनुसार भारत जैसी स्थिति वाले देश में जनसंख्या वृद्धि दर का आर्थिक विकास एवं प्रति व्यक्ति जीवन स्तर पर निश्चय ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा । जनसंख्या वृद्धि की इस गति से योजना आयोग के सभी अनुमान गलत सिद्ध हो जाते हैं । परिणामस्वरूप आर्थिक विकास से मिलने वाले लाभ समाप्त हो जाते हैं । इस प्रकार देश की आर्थिक एवं सामाजिक सफलता वस्तुत: उपयुक्त जनसंख्या नीति पर निर्भर करती है ।

जनसंख्या नीति का अर्थ तथा परिभाषाएं

जनसंख्या नीति से तात्पर्य उस शासकीय नीति से है जिसके अनुसार वह अपने देश के साधनों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या के आकार को प्रभावित करती है । जनसंख्या नीति सभी देशों में समान नहीं होती इसकी प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं:

- **पीसी जैन के अनुसार:** जनसंख्या नीति केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विचारपूर्वक बनाई गई और क्रियान्वित की गई नीति होती है । इसका प्रमुख उद्देश्य प्रजनन क्षमता को घटाकर जनसंख्या की वृद्धि दर को घटाना है ।
- **एस चंद्रशेखर के अनुसार:** जनसंख्या नीति सरकार द्वारा देश की जनसंख्या के आकार तथा संगठन में किसी सरकारी नियम या निर्देश द्वारा परिवर्तन लाने के लिए किया गया प्रयास है ।
- **टेराओ के अनुसार:** जनसंख्या समस्या हल करने हेतु जो उपाय किए जाते हैं उन्हें जनसंख्या नीति के अंतर्गत रखा जाता है । इस नीति में मुख्यतः जनसंख्या वृद्धि अथवा निरोध दोनों ही सम्मिलित किए जाते हैं ।
- **मिर्डल के अनुसार:** एक जनसंख्या नीति किसी भी प्रकार से सामाजिक नीति से कम नहीं होती । यदि व्यवहारिक सामाजिक विज्ञान सजग नहीं है, तब यह खतरा है कि जनसंख्या नीति अविवेक पूर्ण रूप से संकीर्ण हो जाएगी तथा यह निदानो का उपहास होगा । एक जनसंख्या कार्यक्रम को संपूर्ण सामाजिक जीवन में ताने-बाने में बुना जाना चाहिए तथा उसे समस्त सामाजिक परिवर्तनों द्वारा सामाजिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए । यदि हमारी प्रतिक्रियाए विवेकपूर्ण है तब जनसंख्या संकट हमें सामाजिक उद्देश्यों तथा कार्यक्रमों पर पुनर्विचार करने को बाध्य करता है ।

A Population Policy can be nothing less than a social change at large. If practical social science is not on watch there is a palpable danger that Population Policy will be irrationally narrowed down and forced into remedial quackery. A population program must work itself into the whole fabric of social life and must interpenetrate and be interpenetrated by all other measures of social change. The population crisis must if we are to react, rationally make as thing all social objectives and programme.

- यूनेस्को द्वारा गठित जनसंख्या आयोग के अनुसार: जनसंख्या नीति के अंतर्गत वे सभी उपाय और कार्यक्रम शामिल होते हैं जो विशिष्ट जनांकिकीय चरों जैसे जनसंख्या के आकार एवं वृद्धि, उसके भौगोलिक वितरण एवं जनांकिकीय विशेषताओं को प्रभावित करते हुए आर्थिक, सामाजिक, जनांकिकीय, राजनीतिक एवं अन्य सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योगदान करने हेतु तैयार किए जाते हैं।

  Population policy includes the measures and programmes designed to contribute to the achievement of economic, social, demographic, political and other collective goals through affecting critical demographic variables namely, the size and growth of population, its geographical distribution and its demographic characteristics.

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक उपयुक्त जनसंख्या नीति के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य होने चाहिए:

1. देश की आवश्यकतानुसार जनसंख्या में वृद्धि या कमी करना
2. ऐसी सुनियोजित जनसंख्या नीति जो तीव्र गति से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करें
3. जनसंख्या में गुणात्मक सुधार तथा
4. मृत्यु दर में कमी लाना
5.

भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या के आकार की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है कि जनसंख्या नीति, जनसंख्या नियंत्रण अथवा जन्म नियंत्रण नीति का पर्यायवाची बन गया है ।

भारत की तुलना पाश्चात्य देशों से नहीं की जा सकती है । वहां 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक थे । इन दोनों में औद्योगिक क्रांति के बाद लोगों में ऊँचे जीवन स्तर की आकांक्षाएं जागृत हुईं । इसके अतिरिक्त समाज में महिलाओं के स्थान में भी परिवर्तन हुआ तथा शिशुओं के लालन-पालन के व्यय में भी वृद्धि हो गई । इससे लोगों को छोटे परिवार की अवधारणा को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा ।

भारतीय जनसंख्या नीति का निर्धारण बहुत सोच-समझकर किया गया । इस समय देश के सम्मुख विश्व की विभिन्न जनसंख्या नीतियों में से 2 देशों की जनसंख्या नीति के उदाहरण थे - इंग्लैंड तथा रूस । इंग्लैंड में जनसंख्या नीति *जन्म नियंत्रण नीति* के नाम से जानी जाती है । यह जनसंख्या नीति व्यक्तिवादी है जबकि रूस की जनसंख्या नीति राष्ट्रवादी है क्योंकि वहां जनसंख्या नीति का निर्धारण राष्ट्र हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है ।

भारत की जनसंख्या नीति मिश्रित है । भारत में जन्म नियंत्रण कार्यक्रम का नया नाम परिवार नियोजन तथा बाद में परिवार कल्याण रखा गया है । यहां परिवार नियोजन की सफलता लोगों के इस कार्यक्रम

को स्वेच्छा से स्वीकार करने पर निर्भर करती है । इस दृष्टि से सरकार लोगों को छोटे परिवार के विभिन्न लाभों के संबंध में जानकारी प्रदान करती है तथा अनेक प्रकार से प्रेरित करने का प्रयास करती है । भारत की जनसंख्या नीति का दर्शन निम्नलिखित है:

1. समाज को इन सेवाओं की आवश्यकता का अनुभव करना चाहिए था तथा जब वे प्रदान की जाए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए ।
2. केवल माता-पिता को ही यह निश्चय करना चाहिए कि वह कितनी संताने चाहते हैं ।
3. लोगों के पास ऐसे माध्यम से पहुंचना चाहिए जिनका वे सम्मान करते हो तथा लोगों के विश्वस्त नेताओं के माध्यम से ही उन तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए ।
4. लोगों के घरों से जितना अधिक निकट संभव हो सेवाओं को प्रदान करना चाहिए ।
5. ये सेवाएं उस समय अधिक महत्वपूर्ण होंगी जब इनको चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का अंग बना दिया जाए ।

भारत की प्रथम जनसंख्या नीति का निर्माण 1948 में हुआ । प्रारंभ में परिवार नियोजन पर बल दिया गया । उसके बाद परिवार कल्याण की अवधारणा विकसित हुई । 1974 में बुखारेस्ट में जनसंख्या पर हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में विकासशील देशों में जनसंख्या नियंत्रण हेतु विशेष कदम उठाने पर बल दिया गया । इसके बाद भारत में भी 1976 में नई जनसंख्या नीति आई जिसमें मात्रात्मक लक्ष्यों को हासिल करने पर अत्यधिक जोर दिया गया था । भारत में अब तक 2 राष्ट्रीय जनसंख्या नीतियां 1976 तथा 2000 में बनाई गई । .....क्रमशः

****

सन्दर्भ: जनसँख्या भूगोल-SBPD प्रकाशन, डॉ चतुर्भुज ममोरिया & डॉ एच एस गर्ग; भारत का भूगोल-कॉसमॉस प्रकाशन, महेश बर्णवाल

****